Research Paper | Economics | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 10 | Issue : 9 | September 2024

सार्वजनिक बैंकों की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सफलता में भूमिका

एस. बी. अभंग

सहायक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, श्री. छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय, श्रीगोन्दा, अहमदनगर. महाराष्ट्र

ABSTRACT

भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के विकास और वित्तियन कि कमी दूर करने के लिए 8 एप्रिल 2015 को सिडबी के एक पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी के रूप में मुद्रा (MUDRA) यांनी **'माइक्रो यूनिट्स् डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड'** स्थापित किया है। वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत देशभर शिशु, किशोर और तरूण श्रेणी के तहत सार्वजनिक, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण, सहकारी, स्मॉल फायनान्स बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई क्षेत्र को ऋण दिए जा रहे है। 2015–16 से 2021–22 इस अध्ययन अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सफलतापूर्ण, सक्रियता से प्रतिभागिता कि है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वर्तमान में इस योजना के तहत शिशु श्रेणी के अंतर्गत वितरित ऋण में बढोत्तरी, मुद्रा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार इन बिन्दुओं पर लक्ष्य केंन्द्रित करेंगे, तो व्यवसाय, स्वरोजगार एवं छोटे उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता एवं सहयोग मिलेगा। इस तरह से भविष्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।

KEYWORDS: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम.

प्रस्तावनाः

भारत कि अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों कि महत्वपूर्ण भूमिका है। औद्योगिक विकास, निर्यात, विदेशी मुद्रा कि कमाई और रोजगार निर्माण में भी इस क्षेत्र का कार्य उल्लेखनीय है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है तथा निर्यात में इनकी भागिदारी लगभग 35 प्रतिशत है। समग्र औद्योगिक उत्पाद में भी इन उद्यमों कि भागिदारी 42 से 45 प्रतिशत है।[1] 2013 में एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 5.77 करोड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यरत है।

भारत कि अर्थव्यवस्था में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद इनको कई समस्याएं और चुनोतियों का सामना करना पडता है, जैसे वित्त का अभाव, कौशल विकास का अभाव, कच्चे माल कि समस्या, तकनिकी, विपणन एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, सरकारी नितियों की जानकारी न होना, बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि प्रमुख है।[2] इस क्षेत्र के विकास और वित्तियन की कमी दूर करने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडीया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया, तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे कई कदम उठाए। इन योजनाओं में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन देते हुए उन्हें समाज कि मुख्य धारा में लाना है।[3]

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः परिचय

भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बैंकींग प्रणाली से जोडने, असंगठीत क्षेत्र में कार्यरत छोटे उद्योगों को बैंक से ऋण उपलब्ध करने के लिए मुद्रा (MUDRA) यानी **'माईक्रो यूनिट्स् डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड'** कि 8 एप्रिल 2015 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।[4] वर्तमान में इसकी अधिकृत पूँजी 1000 करोड रुपए और प्रदत्त पूँजी 750 करोड़ रुपए है। मुद्रा बैंक एक एजेंसी के रुप में कार्य करती है, जो विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में संलग्न सूक्ष्म, लघु कोरोबारी संस्थानों को वित्तियन करनेवाले संस्थानों का सहयोग और उनके साथ साझेदारी करती है। वर्तमान में (2021–22) मुद्रा योजना के तहत 27 सार्वजनिक बैंको, 18 निजी बैंकों, 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, 36 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, 29 गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थाओं और 10 स्मॉल फायनान्स बैंकोंद्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ऋण कि सुविधा प्रदान कि है।[5]

मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण कि सुविधा तीन चरणों में दी गई है। शिशु श्रेणी–50,000 रुपए तक के ऋण, किशोर श्रेणी–50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक के ऋण और तरुण श्रेणी के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते है। तीनों श्रेणीयों में सर्वाधिक ध्यान शिशु श्रेणी के इकाइयों पर दिया गया है। कुल ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत ऋण शिशु श्रेणी इकाइयों को दिया जाए, ताकि इन योजनाओं के तहत सूक्ष्म उद्यमों का विकास हो सकें। इस योजना के तहत महिला उद्यमी योजना, मुद्रा कार्ड, बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना, क्रेडिट गारंटी, अल्प ऋण योजना आदि के माध्यम सें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध किया जाता है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अगस्त 2015 से शुरु हुई।6 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समाज के पिछड़े वर्ग को उद्यमी बनाने कि दिशा में एक अच्छा कदम है।

Copyright© 2024, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

इस योजना के सहयोग से सूक्ष्म, लघू और मध्यम क्षेत्र को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन देते हुए, आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

समस्या का चयनः

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पिछले आठ साल से देशभर चल रही है। इस योजना कि सफलता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितनी सक्रियता से प्रतिभागिता करते है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी के अंतर्गत कितने ऋण एम.एस.एम.ई क्षेत्र को वितरित किए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतू 'सार्वजनिक बैंकों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सफलता में भूमिका' इस अध्ययन विषय का चयन किया है।

शोध प्रविधीः

प्रस्तुत अध्ययन द्वितियक संमकों पर आधारित है। द्वितियक संमकों का संकलन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वार्षिक रिपोर्ट (2015–16 से 2021–22), प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं एवं शोध पत्रों के माध्यम से किया है। अध्ययन कि समयावधि 2015–16 से 2021–22 तक सिमित है। विश्लेषण के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया है। सार्वजनिक बैंकों द्वारा कुल वितरित ऋण, कुल स्विकृत आवेदन, शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणीवार स्विकृत आवेदन एवं ऋण यह विश्लेषण के प्रमुख आधार है।

सार्वजनिक बैंको कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कि सफलता में भूमिकाः

आमतौर पर सरकारी योजनाओं कि सफलता इस बातपर निर्भर है कि इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितनी सक्रियता से प्रतिभागिता करते है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कि सफलता में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों द्वारा अब तक कुल वितरित ऋण, कुल स्विकृत आवेदन, शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणीवार स्विकृत आवेदन एवं वितरीत ऋणों का विवरण निम्न लिखित है।

1 मंजूर ऋणों कि संख्या एवं वितरित राशि :

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर ऋणों कि संख्या एवं वितरित राशि कि जानकारी सारणी 1 में दर्शायी है। 2015–16 से 2020–21 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर ऋणों कि संख्या (6607577 से 8060595 तक) और संवितरित राशि में (56127.10 करोड रुपए से 102590.36 करोड़ रुपए तक) निरंतर बढोत्तरी हुई है। लेकिन उसके बाद वित्तिय वर्ष 2021–22 में मंजूर ऋणों कि संख्या (6121790) और संवितरित राशि (98556.10 करोड़ रुपए) में घट हुई है। उपर्युक्त अवधि में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल मंजूर ऋणों कि संख्या और कुल संवितरित राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान क्रमशः 18.94 प्रतिशत से 11.38 प्रतिशत तक और 42.21 प्रतिशत से 29.74 प्रतिशत तक कम हुआ है। इसके बावजूद प्रधान मंत्री मुद्रा योजना कि सफलता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों कि भूमिका महत्वूपर्ण है।

सारणी 1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मंजूर ऋणों कि संख्या एवं संवितरित राशि (2015–16 से 2021–22)

वित्त वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा मंजूर ऋणों कि संख्या	कुल मंजूर ऋणों कि संख्या	प्रतिशत (:)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकोंद्वारा संवितरित राशि (करोड रुपए)	कुल संवितरित राशि (करोड रुपए)	प्रतिशत (:)
1	2	3	4	5	6	7
2015–2016	6607577	34880924	18.94	56127.10	132954.73	42.21
2016–2017	4812137	39701047	12.12	68448.32	175312.13	39.04
2017–2018	5133674	48130593	10.66	87630.49	246437.40	35.56
2018–2019	6664269	59870318	11.13	93366.91	311811.38	29.94
2019–2020	7981168	62247606	12.82	94179.19	329715.03	28.56
2020–2021	8060595	50735046	15.89	102950.36	311754.47	33.00
2021–2022	6121790	53795526	11.38	98556.10	331402.20	29.74

स्त्रोतः Mudra.org वेबसाईट पर PMMY-Bank wise Performance 2015.16 से 2021.22

2 शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी के अंतर्गत मंजूर ऋणों कि संख्याः

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन श्रेणीयों में ऋण दिए जाते है। अध्ययन अवधि में (2015–16 से 2021–22) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल मंजूर ऋणों कि संख्या में शिशु श्रेणी के अंतर्गत मंजूर ऋणों कि संख्या 75.78 प्रतिशत से 57.50 प्रतिशत तक कम हुई है। दुसरी और किशोर श्रेणी और तरुण श्रेणी के अंतर्गत मंजूर ऋणों कि संख्या क्रमशः 19.80 प्रतिशत से 32.10 प्रतिशत तक और 4.42 प्रतिशत से 10.40 प्रतिशत तक बढ़ी है। अध्ययन अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा शिशु श्रेणी के अंतर्गत (सारणी 2) सबसे अधिक 75.78 प्रतिशत ऋण वित्त वर्ष 2015–16 में मंजूर किए गए। वित्त वर्ष 2017–18 और 2021–22 में क्रमशः किशोर श्रेणी (41.30 प्रतिशत) और तरुण श्रेणी (10.40 प्रतिशत) के अंतर्गत सबसे अधिक ऋण मंजूर किए गए।

सारणी 2: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी के अंतर्गत मंजूर ऋणों कि संख्या (2015–16 से 2021–22)

वित्त वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा मंजूर ऋणों कि संख्या			सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर ऋणों कि संख्या
	शिशु श्रेणी	किशोर श्रेणी	तरुण श्रेणी	
1	2	3	4	5
2015–2016	5007578 (75.78)	1307926 (19.80)	292073 (4.42)	6607577 (100.00)
2016–2017	2795155 (58.10)	1627738 (33.80)	389244 (8.10)	4812137 (100.00)
2017–2018	2509392 (48.90)	2119849 (41.30)	504433 (9.80)	5133674 (100.00)

2018–2019	4198061 (63.00)	1903272 (28.56)	562936 (8.44)	6664269 (100.00)
2019–2020	5618668 (70.40)	1808718 (22.66)	553782 (6.94)	7981168 (100.00)
2020–2021	5148348 (63.87)	2257192 (28.00)	655055 (8.13)	8060595 (100.00)
2021–2022	3521675 (57.50)	1963719 (32.10)	636396 (10.40)	6121790 (100.00)

नोटः कोष्टक में दिए आंकडे प्रतिशत दर्शाते है

स्त्रोतः Mudra.org वेबसाईट पर PMMY-Bank wise Performance 2015.16 से 2021.22

3 शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी के अंतर्गत संवितरित राशिः

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अध्ययन अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी कें अंतर्गत संवितरित राशि कि जानकारी सारणी 3 में दर्शायी है। 2015–16 से 2021–22 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकोंद्वारा कुल संवितरित राशि में शिशु श्रेणी और किशोर श्रेणी के अंतर्गत संवितरित राशि का प्रतिशत क्रमशः 14.40 प्रतिशत से 6.30 प्रतिशत तक और 47.35 प्रतिशत से 41. 40 प्रतिशत तक कम हुआ है। दुसरी और तरुण श्रेणी के अंतर्गत संवितरित राशि का प्रतिशत इस अवधि में 37.35 प्रतिशत से 52.30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मुद्रा योजना के नितिगत निर्देश के अनुसार कुल ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत शिशु श्रेणी में दिया जाए। लेकिन उपर्युक्त अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस लक्ष्य को हासिल करने में असफल हुए है

सारणी 3: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी के अंतर्गत संवितरित राशि (2015–16 से 2021–22)

वित्त वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित राशि (करोड रुपए)			सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल संवितरित राशि (करोड रुपए)
	शिशु श्रेणी	किशोर श्रेणी	तरुण श्रेणी	
1	2	3	4	5
2015–2016	8084.57 (14.40)	26579.99 (47.35)	20962.54 (37.35)	56127.10 (100.00)
2016–2017	5636.98 (8.24)	32896.81 (48.06)	29914.53 (43.70)	68448.32 (100.00)
2017–2018	6824.97 (8.00)	42534.40 (48.33)	38271.12 (43.67)	87630.49 (100.00)
2018–2019	10368.19 (11.10)	39974.48 (42.80)	43024.24 (46.10)	93366.91 (100.00)
2019–2020	13781.76 (14.63)	37812.16 (40.15)	42585.27 (45.22)	94179.19 (100.00)
2020–2021	8386.15 (8.15)	44890.80 (43.60)	49673.41 (48.25)	102950.36 (100.00)
2021–2022	6202.32 (6.30)	40785.36 (41.40)	51568.41 (52.30)	98556.10 (100.00)

नोटः कोष्टक में दिए आंकडे प्रतिशत दर्शाते है

स्त्रोतः Mudra.org वेबसाईट पर PMMY-Bank wise Performance 2015.16 से 2021.22

निष्कर्ष एवं सुझाव :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहान देते हूए आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भूमिका महत्वपूर्ण है। अध्ययन अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों कि इस योजना के सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत दी जा रही ऋण राशि में वृध्दी, शिशु श्रेणी के अंतर्गत वितरित ऋण में बढोत्तरी, मुद्रा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार, मुद्रा योजना के लाभार्थीद्वारा समय पर ऋण की वापसी, सरकारद्वारा ब्याज सबसिडी आदि सुझावों पर अंमल किया जाए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा भारत कि अर्थव्यवस्था में भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।

सन्दर्भ

1 सन्तोश श्रीवास्तव (फरवरी 2017), विनिर्माण के क्षेत्र में मुद्रा बैंक योजना का महत्व, सामान्य ज्ञान दर्पण, 46–47।

2 शर्मा, ओ. पी. (1999), भारतीय अर्थव्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियां, सबलाइम पब्लिकेषन्स, जयपूर, पृ. 173–174।.

3 मोनालिसा पवार (2016), मुद्रा योजना की सफलता में सार्वजनिक बैंको की भूमिका, निबंध माला, राज्यसभा सचिवालय, भारत सरकार पृ 23–24।

4 सुबह सिंह यादव (जनवरी – मार्च 2017), मुद्रा योजना, बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, भारतीय रिजर्व बैंक, 29 (2), 37।

5. Govt. of India (2022), PMMY Performance 2021-22, Bank wise Performance, pp.1-3

6 कल्पना एच.ए.(जुलाई–सितंबर 2016), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, भारतीय रिजर्व बैंक, 28 (4), 26–27।

7 भारत सरकार (2017), प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना कि प्रगतीः एक दृश्टी में, मुद्रा बैंक प्रकाषन, मुम्बई।

8 भारत सरकार, मुद्रा बैंक वार्शिक रिपोर्ट 2016–17 से 2021–22।

9. www.mudra.org.in